

Business Bhaskar ND
20/09/2011 P-1

कर बचत इन्फ्रा बांड जारी करने की इजाजत

नई दिल्ली • देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अब भारी-भरकम निवेश की उम्मीद की जा सकती है। सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दीर्घकालीन निवेश आकर्षित करने के लिए आईएफसीआई, एलआईसी, आईडीएफसी और आईआईएफसीएल के साथ-साथ कुछ खास एनबीएफसी को भी चालू वित्त वर्ष के दौरान कर बचत बांड जारी करने की इजाजत दे दी है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय का कहना है कि बीते वित्त वर्ष के दौरान इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जितना वृद्धिपरक निवेश किया गया था उसका अधिकतम 25 फीसदी निवेश ही चालू वित्त वर्ष के दौरान किया जा सकेगा। इसके पीछे मुख्य मकसद देशभर में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का विकास के लिए आवश्यक निवेश आकर्षित करना है। (प्रेंद्र)